भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1624
16 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

स्वदेशी रक्षा उत्पाद का मूल्य

1624. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ सुजय विखे पाटील :
श्री कृष्णपाल सिंह यादव :
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :
डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
डॉ हिना विजयकुमार गावीत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में कितने मूल्य का स्वदेशी रक्षा उत्पादन हुआ है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आगामी तीन वर्षों के दौरान देश में रक्षा पार्क स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूर्ववर्ती बोर्ड से बनाई गई नई स्वतंत्र इकाइयों के लिए विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) : वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन का मूल्य क्रमशः 84,643 करोड़ रु. और 94,846 करोड़ रु. है।

(ख) : रक्षा मंत्रालय रोजगार सृजन से संबंधित आकंड़े नहीं रखता है।

(ग) और (घ) : आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने और 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने देश में दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (डीआईसी), एक उत्तर प्रदेश और

दूसरा तमिलनाडु में स्थापना की है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (यूपीडीआईसी को विकसित करने के लिए 06 (छह) नोड्स अर्थात आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ को चिन्हित किया गया है । इसी प्रकार तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे (टीएनडीआईसी) को विकसित करने के लिए 5 नोड्स अर्थात चैन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सालेम और तिरुचिरापल्ली को चिन्हित किया गया है। सरकार का विचार है कि देश में उत्पादन को बढ़ावा देने और इकोनामी आफ स्केल के सृजन एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक उपक्रमों को विकसित करने की सुविधा के लिए परीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु आपूर्ति श्रृंखला सहित अनुकूल परिस्थितियों से युक्त रक्षा विनिर्माण पारिप्रणाली विकसित की जाए।

यूपीडीआईसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उद्योगों/संगठनों के साथ 105 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनसे 12,139 करोड़ रु. के निवेश की संभावना है । यूपीडीआईसी में पहले ही 2,422 करोड़ रु. का निवेश किया जा चुका है। यूपीडीआईसी के विकास के लिए 1,608 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके अलावा, टीएनडीआईसी के लिए तमिलनाडु से सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 53 उद्योगों द्वारा 11,794 करोड़ रु. की निवेश की संभावना के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से व्यवस्था की गई है। टीएनडीआईसी में 3,847 करोड़ रु. का निवेश पहले ही हो चुका है। टीएनडीआईसी के विकास केवल कुल 910 हैक्टेयर भूमि को अधिग्रहित किया जा चुका है।

(ङ) : तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड से सात नए डीपीएसयू तैयार किए गए हैं जिन्हें अक्टूबर, 2021 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सरकारी कंपनियों (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में) के रूप में शामिल किया गया है। सरकार ने इन नई रक्षा कंपनियों को कार्पोरेट संस्थाओं के रूप में अपना कारोबार शुरू करने में आरंभिक सहायता और समर्थन देने के लिए कदम उठाए हैं। इस संबंध में तत्कालीन ओएफबी के साथ बकाया इन्डेंट्स को शामिल किया गया था और इन्हें अगले पांच वर्षों के लिए 70,776 करोड़ रु. मूल्य की संविदाओं के रूप में माना गया है। इन संविदाओं में उत्पादों के आपूर्ति के लिए वार्षिक लक्ष्य प्रदान किए गए हैं । प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के लक्ष्य से संबंधित 60% धनराशि इन संविदाओं में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार नए डीपीएसयू को अग्रिम के रूप में सेनाओं द्वारा भुगतान की जाएगी। इन अग्रिमों में नवगठित डीपीएसयू के लिए कार्यकारी पूंजी का प्रावधान है। अधिक कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता के साथ ये नए डीपीएसयू रक्षा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के लिए निर्यात सहित अपना ग्राहक आधार विस्तृत करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। ये डीपीएसयू विदेश में विभिन्न भारतीय दूतावासों और मिशनों में रक्षा अताशे के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से निर्यात अवसरों को बढ़ा रहे हैं।

*****